आकाशवाणी केन्द्र शिमला
31.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

पंचायत

प्रदेश की 3 हजार 5 सौ 77 पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इसके बाद आज आधी रात के बाद प्रदेश की सभी पंचायतें अपने आप ही भंग हो जाएगी। प्रदेश में पहली बार फरवरी से पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह दूसरी वैकल्पिक व्यव्सथा लागू होगी। लोकतंत्र की सबसे निचली और सबसे अहम इकाई सरकार के अगले आदेशों के मुताबिक चलाई जाएगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सरकार को मामला भेजा है।

बिंदल

इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर पंचायत चुनावों को जान–बूझ कर टालने का आरोप लगाया है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां छीनने का प्रयास कर रही है जो सही नहीं है। बिंदल ने सरकार से अगले चुनावों तक पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां यथावत बनाए रखने की मांग की है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

देशभर में किसानों को 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। यह योजना केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य भूमि में पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत 93 हजार से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। अभी तक खेतों के 6 लाख से अधिक अवलोकन कार्यक्रम आयोजित हुए और हजारों जागरुकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये उपलब्धियां इस योजना के विस्तार और बढ़ते पैमाने को दर्शाती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर दो वर्ष के अंतराल पर वितरित किए जाते हैं, जिनके माध्याम से भूमि की भौतिक–रसायन जानकारी और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है। ये कार्ड किसानों को फसल आधारित खेती करने, सही मात्रा में उर्वरक और रासायनिक तत्वों् के इस्तेमाल की जानकारी प्रदान करते हैं।

विशेषाधिकार हनन

मंडी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान निर्धारित सरकारी प्रोटोकॉल का पालन न होने पर आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यविधि व कार्य संचालन नियमावली के तहत प्रस्तुत किया गया है। अपने नोटिस में यादविंद्र गोमा ने उल्लेख किया है कि वह 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मंडी पहुंचे थे, लेकिन उनके आगमन के समय न तो उपायुक्त मंडी उपस्थित थे और न ही प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना या आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं।

26 जनवरी का कार्यक्रम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे मंडी जिला में झंडा फहराने के लिए नियुक्त किया गया था। वहां पर जब मैं पहुंचा तो सब लोग, सभी कार्यकर्ता, अधिकारी, एसपी, एडीसी, सारा स्टाफ जबकि उपायुक्त मंडी वहां पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने मुझे इस विषय में कोई भी मैसिज कनवे नहीं किया था मैने अपने कुलिग से भी इस विषय पर बातचीत की और परिणाम यह निकला की उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाए ताकि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा न हो।

गृह मंत्रालय–आईजीपी

केंद्र सरकार ने पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक रैंक के भारतीय पुलिस सेवा–आईपीएस अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दो साल का केंद्रीय अनुभव अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। मंत्रालय के अनुसार, यह निर्देश 2011 बैच से आगे के आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा।

डीजीएचएस–नीट

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने आज बताया कि राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा–स्नातकोत्तर राउंड 3 काउंसलिंग प्रक्रिया फिर शुरू हो चुकी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निदेशालय ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया नए पंजीकरणों की सुविधा के साथ पात्र उम्मीदवारों को और अवसर प्रदान करते हुए अतिरिक्त सीटें भी शामिल की गई हैं। पात्र उम्मीरदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने और तदनुसार विकल्प चुनने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

————————————